चुनौती हर साल हजारों ग्रेजुएट्स तैयार करने के बाद भी कॉर्पोरेट इकोसिस्टम को तरस रहा शहर, स्किल-बेस्ड एजुकेशन की कमी सबसे बड़ी चुनौती

आखिर क्यों जबलपुर नहीं आ रही हैं बड़ी कंपनियां?

मोहम्मद जुनैद खान

नवभारत, जबलपुर। भौगोलिक रूप से देश के केंद्र में बसने और मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी होने के बावजूद जबलपुर पिछले कुछ समय से प्राइवेट सेक्टर के निवेश में पीछे छूट गया है। जहाँ इंदौर और भोपाल में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है, वहीं महाकौशल का प्रमुख केंद्र होने के बावजूद जबलपुर नई प्राइवेट कंपनियों को आकर्षित करने में संघर्ष कर रहा है। कमर्शियल उपयोग के लिए बड़े भूखंडों की कमी, विकास नीतियों का क्षेत्रीय असंतुलन और कुशल युवाओं का अन्य महानगरों की ओर पलायन इसके मुख्य कारण हैं। यह स्थिति अब शहर के आर्थिक भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

सरकारी नौकरी माइंडसेट और इकोसिस्टम की कमी

दशकों से जबलपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से गन कैरिज फैक्ट्री, ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया और पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय जैसे सरकारी व रक्षा संस्थानों के इर्द-गिर्द सिमटी रही है। इन सुरक्षित नौकरियों के कारण स्थानीय युवाओं में एक गहरा 'सरकारी नौकरी वाला माइंडसेट' विकसित हो गया, जिससे यहाँ नया रिस्क उठाने और प्राइवेट कॉर्पोरेट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति बेहद कम रही। चूंकि रक्षा क्षेत्र का अपना एक बंद प्रोक्योरमेंट सिस्टम (आपूर्ति श्रृंखला) होता है, इसलिए स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र प्राइवेट वेंडर्स और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का व्यापक नेटवर्क कभी तैयार ही नहीं हो पाया है।

व्यावहारिक स्किल आधारित शिक्षा की भारी कमी

जबलपुर में थ्योरिटिकल और पारंपरिक डिग्रियों का चलन तो है, लेकिन आज की कॉर्पोरेट कंपनियों की मांग के अनुसार प्रैक्टिकल और स्किल-बेस्ड एजुकेशन (कौशल आधारित शिक्षा) की भारी कमी है। यहाँ के कई प्रमुख संस्थानों का पाठ्यक्रम पुराने ढर्रे पर चल रहा है, जिससे ग्रेजुएट्स के पास आधुनिक कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, और एआई जैसी जरूरी इंडस्ट्री स्किल्स नहीं होतीं है। यह ठहराव प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुन्नार मायर्डल के 'सर्कुलर कॉजेशन' सिद्धांत को

दिखाता है, इस आर्थिक दुष्चक्र के हिसाब से यहाँ कॉर्पोरेट माहौल और स्किल ट्रेनिंग की कमी से टैलेंट नहीं रुकता, और टैलेंट न रुकने की वजह से बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां निवेश नहीं करतीं। यह कमी आंकड़ों में भी साफ दिखती है, ट्रिपल आईटीडीएम जैसे चुनिंदा बड़े संस्थानों के लगभग 66 प्रतिशत से अधिक ऑफर्स 10 लाख रुपये सालाना पैकेज से ऊपर के होते हैं और जेइसी में भी सालाना 350 से ज्यादा छात्रों का प्लेसमेंट होता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर एडवांस स्किल ट्रेनिंग हब्स और बड़े टेक पार्क्स न होने से इन गिने-चुने टैलेंटेड युवाओं को भी रोजगार के लिए मजबूरन तुरंत शहर छोड़कर मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे महानगरों में जाना पड़ता है।

लैंड बैंक संकट और कमजोर कनेक्टिविटी

किसी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लगाने के लिए सैकड़ों एकड़ विवाद-मुक्त और एकमुश्त जमीन की जरूरत होती है, जिसकी जबलपुर में भारी किल्लत है। इसके साथ ही, नेपियर टाउन और राइट टाउन जैसे मुख्य कमर्शियल क्षेत्रों में ब्रिटिश काल के जटिल जमीन लीज नियम आज भी प्रभावी हैं, जिनके कानूनी विवादों के डर से कॉर्पोरेट कंपनियां यहाँ आने से कतराती हैं। इसके अलावा, आधुनिक ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस की कमी और डुमना एयरपोर्ट से प्रमुख बिजनेस शहरों के लिए सीमित हवाई उड़ानों के कारण वरिष्ठ अधिकारियों का तुरंत आना-जाना मुश्किल होता है, जिससे कंपनियाँ रायपुर या नागपुर को प्राथमिकता देती हैं।

क्षेत्रीय नीति असंतुलन और वर्तमान सुधार

राज्य की औद्योगिक नीतियों और बड़े निवेश सम्मेलनों का मुख्य फोकस हमेशा से पश्चिमी मध्य प्रदेश की इंदौर-पीथमपुर औद्योगिक बेल्ट की तरफ अधिक रहा है। प्रशासनिक स्तर पर जबलपुर की क्षमताओं को आक्रामकता से पेश न किए जाने के कारण इसे लंबे समय तक केवल एक शांत 'न्यायिक केंद्र' माना गया, जिससे यह निवेशकों की प्राथमिकता सूची में ऊपर नहीं आ सका। हालांकि, इस गतिरोध को तोड़ने के लिए राज्य सरकार की नई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) पॉलिसी के तहत वित्तीय रियायतें दी जा रही हैं और जबलपुर मास्टर प्लान 2041 के 114 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट से आने वाले समय में माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।

इनका कहना है

रोजगार के अवसर नहीं मिलने की वजह से टैलेंटेड युवा बाहर जाते है और स्किल्ड युवा न मिलने की वजह से कंपनियां यहां नहीं आती है। अगर इस दुष्चक्र को तोड़ना है तो युवाओं को लेटेस्ट इंडस्ट्री स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। साथ ही सरकार को अपनी नीतियों में सुधार कर उद्योग पर ज्यादा फोकस करना होगा और शहर के उद्योगपतियों व आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों को लोकल टैलेंट में भारी निवेश करना होगा।

प्रेम दुबे
प्रेसिडेंट, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

शहर में बिजनेस ग्रोथ कम होने और स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलने की वजह से कंपनियां यहां आने से कतराती है। यहां तक कि ग्रोथ का स्कोप कम होने और आईटी पार्क शहर से बहुत दूर होने की वजह से शहर के अधिकांश फाउंडर्स अपने स्टार्टअप अन्य महानगरों में जाकर करते है। शहर में प्राइवेट जॉब की पेइंग कैपेसिटी कम होने से टैलेंटेड युवा बाहर जाते है। अगर इस सिचुएशन से शहर को निकालना है तो सरकार और उद्योगपतियों को स्थानीय प्रतिभाओं में बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी।

भरत गुप्ता
फाउंडर, सोशियो भारत

सेंट्रल जीएसटी का तत्कालीन अधीक्षक निकला धनकुबेर

सीबीआई ने दर्ज की आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर

नवभारत, जबलपुर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जबलपुर ने सेंट्रल जीएसटी डिवीजन-1 के तत्कालीन अधीक्षक मुकेश कुमार बर्मन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण दर्ज कर लिया है। रिश्वतखोरी प्रकरण की विस्तृत जांच में आरोपी धनकुबेर निकला। आरोपी अधिकारी ने बीते कुछ वर्षों में अपने और अपने परिजनों के नाम पर भारी बेनामी संपत्तियां खड़ी की हैं। विदित हो कि सीबीआई जबलपुर ने 16 दिसंबर 2025 को सीजीएसटी कार्यालय के इंस्पेक्टर सचिन खरे और अधीक्षक मुकेश कुमार बर्मन सहित अन्य अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दज्र किया गया था। ट्रैप की कार्रवाई के तुरंत बाद 17 दिसंबर 2025 को आरोपी अधीक्षक मुकेश कुमार बर्मन के आवासीय परिसरों पर छापेमारी की गई थी। तलाशी के दौरान अचल संपत्तियों के दस्तावेज, विलासिता से जुड़े खर्चों के बिल, वेतन विवरण और बैंक खातों की पासबुक जब्त की गईं। रिश्वतखोरी के मामले की विस्तृत स्क्रूटनी के बाद जांच में सामने आया है कि आरोपी अधिकारी ने बीते कुछ वर्षों में अपने और अपने परिजनों के नाम पर भारी बेनामी संपत्तियां खड़ी की हैं। जांच एजेंसी ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आपराधिक मामला दर्ज किया है।

6 साल की काली कमाई

बैंकों और दफ्तरों से मिले दस्तावेजों की गहन जांच में यह बात सामने आई है कि बर्मन ने 1 जनवरी 2019 से 17 दिसंबर 2025 के बीच अपने पद का दुरुपयोग कर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अवैध संपत्ति अर्जित की है। सीबीआई ने आरोपी अधीक्षक की इस काली कमाई का पूरा लेखा-जोखा तैयार किया है।

89 प्रतिशत से अधिक मिली बेनामी संपत्ति

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई द्वारा की जांच मं यह बात सामने आई कि मुकेश कुमार बर्मन के 1 जनवरी 2019 से लेकर 17 दिसम्बर 2025 तक के सेवा कार्यकाल के दौरान जुटाए गए गोपनीय और वित्तीय दस्तावेजों की बारीकी से स्कूटनी की गई। जांच में यह बात सामने आई कि इस अवधि के दौरान अधिकारी ने अपने वैध आय के ज्ञात स्रोतों से इतर कुल 92,33,324 रुपये की अनुपातहीन संपत्ति का साम्राज्य खड़ा किया। यह बेनामी संपत्ति उनके कुल कानूनी आय स्रोतों के मुकाबले 89.36 प्रतिशत अधिक पाई गई है, जिसका अधिकारी के पास कोई संतोषजनक हिसाब नहीं था।

गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, वज्रपात का अलर्ट

जुलाई में अब तक 204.4 मिमी वर्षा दर्ज, अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम

जबलपुर। शहर में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस सामान्य के बराबर रहा। पिछले 24 घंटों में 6 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि सुबह

8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 20.6 मिमी बारिश दर्ज हुई। चालू मानसून सीजन में अब तक जिले में 204.4 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है।

मौसम विभाग के अनुसार जिले में सोमवार को भी अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसारदक्षिण-पश्चिम दिशा से 4 से 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं कुछ स्थानों पर वज्रपात और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है।

डकैत से पूछताछ, गोल्ड रखने वाला गया जेल, 14 करोड़ की बैंक डकैती में मददगारों की तलाश

नवभारत,जबलपुर। खितौला अंतर्गत ईसाफ स्मॉल फाईनेंस बैंक में हुई अंतर्राज्यीय बैंक डकैती मामले में गिरफ्तार डकैत सुनील पासवान पिता नरेश पासवान 38 वर्ष निवासी ग्राम बनाही आमस जिला गया बिहार को पुलिस आठ दिन की रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है । जबकि दो दिन की रिमांड खत्म होने पर डकैती का माल रखने वाले चंचल पासवान पिता ननकू पासवान 38 वर्ष निवासी गुरूवा हब्बीपुर थाना गुरूवा जिला गया बिहार को पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया

जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस गिरफ्त में आए पांचवें डकैत से 14 करोड़ की बैंक डकैती में मद्दगारों, सुनारो की जानकारी जुटा रही है । साथ ही गोल्ड रिकवरी के प्रयास किए जा रहे है। विवाद हो कि खितौला अंतर्गत ईसाफ स्मॉल फाईनेंस बैंक में 11 अगस्त 2025 को डकैती पड़ी थी। जिसमें 14 किलो 800 ग्राम सोने के जेवरात और लगभग 5 लाख रुपए डकैत लूट कर ले गए थे। अंतर्राज्यीय बैंक डकैती के सरगना और उसके अन्य 10 साथियों को पूर्व में तकनीकी सहायता से बिहार एवं मध्यप्रदेश से पूर्व में गिरफ्तार कर 3 किलो से अधिक सोना जब्त किया जा चुका है। अब दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या 13 हो गई है।

राजगढ़ पुलिस भी करेगी गिरफ्तार

डकैत चंचल पासवान पिता ननकू पासवान ने छत्तीसगढ़ के राजगढ़ में चार से पांच करोड़ की बैंक डकैती डाली थी। इस डकैती में भी वे फरार था। डकैत सुनील के खिलाफ अगल अलग राज्यों में पूर्व से लूट एवं डकैती के 9 गम्भीर अपराध दर्ज है और वे मध्यप्रदेश के जबलपुर , झारखण्ड, छत्तीसगढ एवं बिहार राज्य से बैंक डकैती के अलग-अलग मामलों में फरार चल रहा था।

सुनारों को बेचा गोल्ड, पुलिस की छापेमारी जारी

डकैत सुनील पासवान ने पूछताछ में बताया कि उसे हिस्से में डेढ किलो सोने के जेवरात बैंक डकैती के हिस्से से मिला था जिसका आधा सोना लगभग 750 ग्राम अपने परिचित चंचल पासवान निवासी गुरूवा को 45 लाख रूपये में बेचा एवं शेष 750 ग्राम सोना सवा करोड़ रुपए का दो अलग अलग सुनार को बेचना बताया है। सूत्रों की माने तो पुलिस को सुनारों के नाम उनके ठिकानों का पता लगा है और पुलिस की टीम गोपनीय तरीके से छापेमारी भी कर रही है ।

एमबीबीएस इंटर्न का फूटा गुस्सा, स्टायफंड बढ़ाने के लिए निकाली शांतिपूर्ण पदयात्रा

नवभारत,जबलपुर। चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस इंटर्न और भावी डॉक्टरों ने स्टायफंड में बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के इंटर्न ने देश के विभिन्न राज्यों का तुलनात्मक डेटा जारी कर बताया कि मध्य प्रदेश में इंटर्न्स का आर्थिक शोषण हो रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कम मिल रहे स्टाइपेंड पर गहरी नाराजगी जताई। अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए इंटर्न्स ने अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत डॉक्टरों ने एक शांतिपूर्ण पैदल यात्रा का आयोजन किया।

यह पदयात्रा पूरी तरह अनुशासित और कॉलेज के कार्य समय के बाद निकाली गई। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि इस दौरान अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षणिक गतिविधियों में कोई रुकावट नहीं आने दी गई। छात्रों ने अधिष्ठाताओं के माध्यम से मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपे हैं।

जूडा की प्रमुख मांगें

न्यूनतम 30,000 स्टाइपेंड किया जाए। वर्तमान में मिल रहे 14,337 को तुरंत बढ़ाया जाए। हर साल स्टाइपेंड में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए। निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों का भेदभाव खत्म हो। महंगी पढ़ाई के मुकाबले स्टाइपेंड को तर्कसंगत बनाया जाए। मांगों का ज्ञापन तहसीलदार रघुवेन्द्र पटेल को दिया गया ।

शिक्षा के व्यापारीकरण का रास्ता खोल रही सरकार : एवीबीपी

निजी विवि संशोधन विधेयक का किया विरोध

नवभारत, जबलपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकोशल प्रांत ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक-2026 का कड़ा विरोध करते हुए इसे उच्च शिक्षा के व्यापारीकरण की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार परिषद का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानकों में ढील मिलेगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और विद्यार्थियों के हित प्रभावित होंगे।

परिषद ने आरोप लगाया की विधेयक में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए निर्धारित 25 एकड़ भूमि की अनिवार्यता को हटाकर उसकी जगह 'पर्याप्त भूमि' जैसा अस्पष्ट प्रावधान किया जा रहा है। परिषद के अनुसार यह शब्दावली मनमानी व्याख्या, पक्षपात और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को बढ़ाएगी तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए तय न्यूनतम मानकों को कमजोर करेगी। परिषद ने अपने विरोध के समर्थन में यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ (2005) तथा आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी (2025) के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा की शीर्ष अदालत ने विश्वविद्यालयों के लिए पर्याप्त भूमि, स्थायी परिसर और मजबूत शैक्षणिक अधोसंरचना को अनिवार्य माना है। ऐसे में प्रस्तावित संशोधन न्यायालय की मंशा के विपरीत प्रतीत होता है। परिषद का कहना है की राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता अवश्य है, लेकिन केवल निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी। परिषद ने आशंका जताई की मानकों में ढील का सीधा असर विद्यार्थियों के भविष्य और प्रदेश की उच्च शिक्षा की विश्वसनीयता पर पड़ेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा की यह संशोधन उच्च शिक्षा के भविष्य से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है। उनके अनुसार 'पर्याप्त भूमि' जैसे अस्पष्ट प्रावधान शिक्षा के व्यापारीकरण और निजी व्यावसायिक हितों को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बाजार की वस्तु नहीं बनाया जा सकता और उच्च शिक्षा में किसी भी सुधार का आधार गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा विद्यार्थियों का हित होना चाहिए, न कि व्यावसायिक लाभ। परिषद ने स्पष्ट किया की वह शिक्षा को सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण का माध्यम मानती है। इसी सोच के तहत संगठन ने प्रस्तावित संशोधन विधेयक का स्पष्ट विरोध करते हुए सरकार से इसे पुनर्विचार के लिए वापस लेने और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने की मांग की है।

तालाब में डूबने से युवक की मौत

नवभारत,जबलपुर। सिहोरा थाना अंतर्गत ग्राम गुनहरु मोहसाम में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक शनिवार शाम से लापता था।

जानकारी अनुसार सागर कोल उर्फ आकाश पिता फूलचंद कोल सागर 23 वर्ष को लगभग 8 वर्ष से मिर्गी आती थी जिसका इलाज चल रहा था लेकिन आराम नहीं हुआ था। सागर कोल रोजाना गांव के तालाब में शाम लगभग 6 बजे फ्रेश होने जाता था। शनिवार की शाम भी गया था काफी देर तक सागर घर वापस नहीं आया तो परिजन चिंतित हो गए और उन्होंने खोजबीन शुरू की। तलाश के दौरान ग्रामीणों ने जानकारी दी कि उन्होंने सागर को शाम के वक्त गांव के तालाब की ओर अकेले जाते हुए देखा था। तालाब के पास युवक के होने की आशंका पर परिजनों ने तत्काल सिहोरा पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और गोताखोरों व ग्रामीणों की मदद से तालाब में खोजबीन शुरू की। काफी प्रयासों और कड़ी मशक्कत के बाद अंततः सागर का शव गहरे पानी से बाहर निकाला जा सका। शुरुआती परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस और ग्रामीणों का अनुमान है कि सागर रात के समय शौच की नियत से तालाब के किनारे गया होगा। अंधेरा होने के कारण अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे गहरे पानी में चला गया। तैरना न आने या संभलने का मौका न मिलने के कारण वह डूब गया।

करंट लगने से बुजुर्ग की मौत, जांच में जुटी पुलिस

जबलपुर। माढ़ोताल थाना अंतर्गत बिलखरवा में करंट लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई। करंट कैसे और किन परिस्थितियोंमें लगा इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है पुलिस मर्ग कायम कर छानबीन कर रही है।

पुलिस के मुताबिक रविवार को सुजीत नट 29 वर्ष निवासी नट बस्ती बिलखिरवा ने सूचना दी कि सुबह लगभग 10-30 बजे वह अपने काम पर चला गया था सुबह लगभग 11 बजे बाजू में रहने वाले सतीश नट ने फोन पर बताया कि पिता को करंट लग गया है उसने घर आकर देखा उसके पिता शिव कुमार नट हाथ में वायर पकड़े मिले मोहल्ले के लोग भी आ गये। पिता शिवकुमार नट की करंट लगने से मौत हो गई है। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज किए जाने के बाद मामला स्पष्ट हो सकेगा जिसके बाद जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

समस्या मूलभूत सुविधाओं की मांग पर अभी नहीं निकला समाधान, बजट खत्म होने की बात कहकर सोमवार की बैठक का दिया आश्वासन

समस्याओं को लेकर शहीद बिरसामुंडा वार्ड 75 के कार्यालय पहुंचे रहवासी

नवभारत, जबलपुर। शहर के शहीद बीरसा मुंडा वार्ड क्रमांक 75 महाराजपुर में सड़क, नाली और पाइपलाइन जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर वार्ड कार्यालय पहुंचे , करीब 10 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे वार्ड नागरिकों का कहना है कि क्षेत्र में कई स्थानों पर सड़क, नाली और पेयजल पाइपलाइन जैसी सुविधाएं आज भी अधूरी हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। रहवासियों की उम्मीद थी कि वे पार्षद से मिलकर अपनी समस्याएं सीधे रखेंगे, लेकिन पार्षद कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। उनके सहयोगी ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष का बजट समाप्त हो चुका है, इसलिए तत्काल नए विकास कार्य शुरू करना संभव नहीं है। सड़क, नाली और पाइपलाइन जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर वार्ड क्रमांक 75 के रहवासी वार्ड कार्यालय पहुंचे। पार्षद से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उनके सहयोगी ने बजट समाप्त होने की जानकारी देते हुए सोमवार सुबह 10:30 बजे बैठक कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

इनका कहना है

यह एक बड़ा विकास कार्य है। हमने विधायक जी को पत्र लिखकर परियोजना की स्वीकृति और बजट की मांग की है। अब स्वीकृति मिलते ही सड़क, नाली और अन्य आवश्यक कार्य शुरू कराए जाएंगे।

लक्ष्मण लक्ष्मी गोटिया
शाहिद बिरसामुंडा वार्ड , पार्षद

हम लोग करीब 10 साल से यहां रह रहे हैं, लेकिन आज तक सड़क, नाली और पाइपलाइन जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। बारिश में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बच्चों और बुजुर्गों का निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार शिकायत की, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। अब उम्मीद है कि इस बार हमारी समस्याओं का समाधान होगा ।

अनीता पासी
स्थानीय निवासी

हम अपनी समस्याओं को लेकर वार्ड कार्यालय पहुंचे थे ताकि पार्षद से मिलकर बात कर सकें, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। हमें बताया गया कि बजट खत्म हो गया है और सोमवार को बैठक होगी। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि सड़क, नाली और पाइपलाइन जैसे जरूरी विकास कार्य जल्द शुरू किए जाएं।

विकास पटेल
स्थानीय निवासी

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57